

In this chapter...

In the last two chapters we have studied how the leaders of independent India responded to the challenges of nation-building and establishing democracy. Let us now turn to the third challenge, that of economic development to ensure well-being of all. As in the case of the first two challenges, our leaders chose a path that was different and difficult. In this case their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring.

इस अध्याय में...

पिछले दो अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र-निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए, अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

In this chapter, we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development.

- **What were the key choices and debates about development?**
- **Which strategy was adopted by our leaders in the first two decades? And why?**
- **What were the main achievements and limitations of this strategy?**
- **Why was this development strategy abandoned in later years?**

इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं :

- विकास को लेकर मुख्य बहसों क्या थीं और इनको लेकर कौन-से अहम फैसले हुए?
- पहले दो दशकों में हमारे नेताओं ने कौन-सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया?
- इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रहीं और इसकी सीमाएँ क्या थीं?
- बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया?

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

What is Left and what is Right?

In the politics of most countries, you will always come across references to parties and groups with a Left or Right ideology or leaning. These terms characterise the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in effecting economic redistribution. Left often refers to those who are in favour of the poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. The Right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy.

क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ?

जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने एसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। 'दक्षिणपंथ' अथवा 'वामपंथ' शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन-सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। 'वामपंथ' से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफ ज़िम्मेदारी करते हैं और इन तबकों को उन्नत पहुँचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। 'दक्षिणपंथ' से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ारमूलक अर्थव्यवस्था के ज़रिए ही प्रगति हो सकती है—यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैरज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves, that the government should play a key role in this. There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. Was it necessary to have a centralised institution to plan for the entire country? Should the government itself run some key industries and business? How much importance was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirements of economic growth?

आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुँह फेरकर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यों कहें कि एक 'विज़न' से बँधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक-सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल, आर्थिक-संवृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले—इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन-सी भूमिका निभाए? इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन ज़रूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक संवृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो एसी सूरत में सामाजिक-न्याय पर कितना ज़ोर देना उचित होगा?

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Each of these questions involved contestation which has continued ever since. Each of the decision had political consequence. Most of these issues involved political judgement and required consultations among political parties and approval of the public. That is why we need to study the process of development as a part of the history of politics in India.

इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करना ज़रूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना ज़रूरी है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Ideas of development

Very often this contestation involves the very idea of development. The example of Orissa shows us that it is not enough to say that everyone wants development. For 'development' has different meanings for different sections of the people. Development would mean different things for example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel and to the Adivasi who lives in that region. Thus any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates.

विकास की धारणाएँ

अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए 'विकास' के अर्थ अलग-अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात-संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात-संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए 'विकास' का अर्थ अलग-अलग होगा। इस कारण 'विकास' से जुड़ी कोई भी 'चर्चा' विवादों से परे नहीं होती।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The first decade after Independence witnessed a lot of debate around this question. It was common then, as it is even now, for people to refer to the 'West' as the standard for measuring development. 'Development' was about becoming more 'modern' and modern was about becoming more like the industrialised countries of the West. This is how common people as well as the experts thought. It was believed that every country would go through the process of modernisation as in the West, which involved the breakdown of traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. Modernisation was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing or underdeveloped.

आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुईं। उस वक्त लोग-बाग 'विकास' की बात आते ही 'पश्चिम' का हवाला देते थे कि 'विकास' का पैमाना 'पश्चिमी' मुल्क हैं। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। 'विकास' का अर्थ था ज़्यादा-से-ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को संवृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। 'विकास' की एसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

On the eve of Independence, India had before it, two models of modern development: the liberal-capitalist model as in much of Europe and the US and the socialist model as in the USSR. You have already studied these two ideologies and read about the 'cold war' between the two super powers. There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. These included not just the leaders of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress. There were very few supporters of the American style capitalist development.

आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमरीका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच 'शीतयुद्ध' का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत-से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमरीकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

This reflected a broad consensus that had developed during the national movement. The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government. It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. There were debates among them. For some, industrialisation seemed to be the preferred path. For others, the development of agriculture and in particular alleviation of rural poverty was the priority.

आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिलकुल साफ़ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ़ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगीकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी था।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Planning

Despite the various differences, there was a consensus on one point: that development could not be left to private actors, that there was the need for the government to develop a design or plan for development. In fact the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world. The experience of Great Depression in Europe, the inter-war reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940s contributed to this consensus.

नियोजन

मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था। यूरोप 'महामंदी' का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था; जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Thus the Planning Commission was not a sudden invention. In fact, it has a very interesting history. We commonly assume that private investors, such as industrialists and big business entrepreneurs, are averse to ideas of planning: they seek an open economy without any state control in the flow of capital. That was not what happened here. Rather, a section of the big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the Bombay Plan.

इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल, यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते; वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूँजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन, भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे 'बॉम्बे प्लान' कहा जाता है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investments. Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after Independence. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. The Prime Minister was its Chairperson. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development.

‘बॉम्बे प्लान’ की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन-सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा—यह एक फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The Early Initiatives

As in the USSR, the Planning Commission of India opted for five year plans (FYP). The idea is very simple: the Government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditure for the next five years. Accordingly the budget of the central and all the State governments is divided into two parts: 'non-plan' budget that is spent on routine items on a yearly basis and 'plan' budget that is spent on a five year basis as per the priorities fixed by the plan. A five year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy.

शुरुआती कदम

सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा-सादा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ़ से एक दस्तावेज़ तैयार करेगी, जिसमें अगले पाँच सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य-सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बाँटा गया। एक हिस्सा गैरयोजना - व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना-व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पाँच साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तसवीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The draft of the First Five Year Plan and then the actual Plan Document, released in December 1951, generated a lot of excitement in the country. People from all walks of life - academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians etc. - discussed and debated the documents extensively. The excitement with planning reached its peak with the launching of the Second Five Year Plan in 1956 and continued somewhat till the Third Five Year Plan in 1961.

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज़ भी जारी किया गया। इससे देश में गहमागहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन-बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज़ों पर व्यापक बहस-मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुँच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The Fourth Plan was due to start in 1966. By this time, the novelty of planning had declined considerably, and moreover, India was facing acute economic crisis. The government decided to take a 'plan holiday'. Though many criticisms emerged both about the process and the priorities of these plans, the foundation of India's economic development was firmly in place by then.

चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी। लेकिन, इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। हालाँकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएँ सामने आईं लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड चुकी थी।

The First Five Year Plan

The First Five Year Plan (1951–1956) sought to get the country's economy out of the cycle of poverty. K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should 'hasten slowly' for the first two decades as a fast rate of development might endanger democracy. The First Five Year Plan addressed, mainly, the agrarian sector including investment in dams and irrigation.

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले दो दशक तक भारत को अपनी चाल 'धीमी' रखनी चाहिए क्योंकि तेज़ रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा ज़ोर कृषि-क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बाँध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Agricultural sector was hit hardest by Partition and needed urgent attention. Huge allocations were made for large-scale projects like the Bhakhra Nangal Dam. The Plan identified the pattern of land distribution in the country as the principal obstacle in the way of agricultural growth. It focused on land reforms as the key to the country's development.

विभाजन के कारण कृषि-क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी था। भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आबंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुँचती है। इस योजना में भूमि-सुधार पर ज़ोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

One of the basic aims of the planners was to raise the level of national income, which could be possible only if the people saved more money than they spent. As the basic level of spending was very low in the 1950s, it could not be reduced any more. So the planners sought to push savings up. That too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people.

जनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊँचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोज़गार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूँजी-भंडार कम था।

Nevertheless, people's savings did rise in the first phase of the planned process until the end of the Third Five Year Plan. But, the rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the First Plan. Later, from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of savings in the country actually dropped consistently.

बहरहाल, नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी । लेकिन, यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई।

Rapid Industrialisation

The Second FYP stressed on heavy industries. It was drafted by a team of economists and planners under the leadership of P. C. Mahalanobis. If the first plan had preached patience, the second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions.

औद्योगीकरण की तेज़ रफ्तार

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया गया। पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूलमंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The government imposed substantial tariffs on imports in order to protect domestic industries. Such protected environment helped both public and private sector industries to grow. As savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries and communication could be developed in the public sector. Indeed, such a push for industrialisation marked a turning point in India's development.

सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल, औद्योगीकरण पर दिए गए इस ज़ोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

It, however, had its problems as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. That apart, as industry attracted more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. The Indian planners found balancing industry and agriculture really difficult. The Third Plan was not significantly different from the Second. Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed an unmistakable “urban bias”. Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted focus on agriculture-related industries rather than heavy ones.

बहरहाल, इसके साथ कुछ समस्याएँ भी थीं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाज़ार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। एसे में खाद्यान्न-संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे-सीधे ‘शहरों’ की तरफ़ हदारी होती नज़र आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ एसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि-आधारित उद्योगों पर ज़ोर दिया जाए।

Key - Controversies

The strategy of development followed in the early years raised several important questions. Let us examine two of these disputes that continue to be relevant.

मुख्य विवाद

शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गईं उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं।

Agriculture versus industry

We have already touched upon a big question: between agriculture and industry, which one should attract more public resources in a backward economy like that of India? Many thought that the Second Plan lacked an agrarian strategy for development, and the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer. Gandhian economists like J. C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialisation.

कृषि बनाम

उद्योग हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कइयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर ज़ोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुँची। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर ज़्यादा ज़ोर था।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Chaudhary Charan Singh, a Congress leader who later broke from the party to form Bharatiya Lok Dal, forcefully articulated the case for keeping agriculture at the centre of planning for India. He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmers and rural population.

चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठायी थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड रही है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Others thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. They argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of foodgrains. The state made laws for land reforms and distribution of resources among the poor in the villages. It also proposed programmes of community development and spent large sums on irrigation projects. The failure was not that of policy but its non-implementation, because the landowning classes had lot of social and political power. Besides, they also argue that even if the government had spent more money on agriculture it would not have solved the massive problem of rural poverty.

कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज़ किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनायी गई थी। राज्य ने भूमि-सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बँटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं हुईं। दरअसल, इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि-संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Public versus private sector

India did not follow any of the two known paths to development – it did not accept the capitalist model of development in which development was left entirely to the private sector, nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. Elements from both these models were taken and mixed together in India. That is why it was described as ‘mixed economy’. Much of the agriculture, trade and industry were left in private hands. The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial interventions in agriculture.

निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र

विकास के जो दो जाने-माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूँजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले-जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘मिश्रित-अर्थव्यवस्था’ कहा जाता है। खेती-किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

A mixed model like this was open to criticism from both the left and the right. Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow. The enlarged public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for private capital, especially by way of installing systems of licenses and permits for investment. Moreover, the state's policy to restrict import of goods that could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper. The state controlled more things than were necessary and this led to inefficiency and corruption.

इस तरह के मिले-जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूँजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने एसी चीजों के आयात पर बाधा आयद की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। एसी चीजों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धाविहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीजें रखी हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी हैं।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Then there were critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that the state did not spend any significant amount for public education and healthcare. The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to go. Thus the state helped the private sector to make profit. Also, instead of helping the poor, the state intervention ended up creating a new 'middle class' that enjoyed the privileges of high salaries without much accountability. Poverty did not decline substantially during this period; even when the proportion of the poor reduced, their numbers kept going up.

कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल, सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त, मदद गरीबों की होनी चाहिए थी लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया 'मध्यवर्ग' उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज्यादा कमी नहीं आई; गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Major Outcomes

Of the three objectives that were identified in independent India, discussed in the first three chapters here, the third objective proved most difficult to realise. Land reforms did not take place effectively in most parts of the country; political power remained in the hands of the landowning classes; and big industrialists continued to benefit and thrive while poverty did not reduce much. The early initiatives for planned development were at best realising the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens. The inability to take significant steps in this direction in the very first stage was to become a political problem. Those who benefited from unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction.

मुख्य परिणाम

आज़ाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियाँ थीं। इनकी चर्चा यहाँ तीन अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुँचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इन के कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Foundations

An assessment of the outcomes of this early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundations of India's future economic growth were laid. Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. These included mega-dams like Bhakhra-Nangal and Hirakud for irrigation and power generation. Some of the heavy industries in the public sector – steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production etc. – were started during this period. Infrastructure for transport and communication was improved substantially. Of late, some of these mega projects have come in for a lot of criticism. Yet much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations.

बुनियाद

नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास-परियोजनाएँ इसी अवधि में शुरू हुईं। इसमें सिंचाई और बिजली-उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा-नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बाँध परियोजनाएँ शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे— इस्पात-संयंत्र, तेल-शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा-उत्पादन आदि—इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढाँच में भी काफ़ी इजाज़त हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी, बाद के समय की आर्थिक संवृद्धि (जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि भी शामिल है) इस बुनियाद के बग़ैर संभव नहीं हो पाती।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति



Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Land reforms

In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at land reforms. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of zamindari. This bold act not only released land from the clutches of a class that had little interest in agriculture, it also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. Attempts at consolidation of land – bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture – were also fairly successful. But the other two components of land reforms were much less successful. Though the laws were made to put an upper limit or ‘ceiling’ to how much agricultural land one person could own, people with excess land managed to evade the law. Similarly, the tenants who worked on someone else’s land were given greater legal security against eviction, but this provision was rarely implemented.

भूमि सुधार

जहाँ तक कृषि-क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत-बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action. This could happen only if the rural, landless poor were mobilised. But the landowners were very powerful and wielded considerable political influence. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws, or, when made into laws, they remained only on paper. This shows that economic policy is part of the actual political situation in the society. It also shows that in spite of good wishes of some top leaders, the dominant social groups would always effectively control policy making and implementation.

कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक-ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। एसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो लेकिन भू-स्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज़ की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भलमनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है।

Food Crisis

The agricultural situation went from bad to worse in the 1960s. Already, the rate of growth of food grain production in the 1940s and 1950s was barely staying above rate of population growth. Between 1965 and 1967, severe droughts occurred in many parts of the country. As we shall study in the next chapter, this was also the period when the country faced two wars and foreign exchange crisis. All this resulted in a severe food shortage and famine – like conditions in many parts of the country.

खाद्य संकट

1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। 1940 और 1950 के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे-तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में भारत ने दो युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

It was in Bihar that the food-crisis was most acutely felt as the state faced a near-famine situation. The food shortage was significant in all districts of Bihar, with 9 districts producing less than half of their normal output. Five of these districts, in fact, produced less than one-third of what they produced normally.

बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से पाँच जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज एक-तिहाई ही अनाज उपजा रहे थे।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Food deprivation subsequently led to acute and widespread malnutrition. It was estimated that the calorie intake dropped from 2200 per capita per day to as low as 1200 in many regions of the state (as against the requirement of 2450 per day for the average person). Death rate in Bihar in 1967 was 34% higher than the number of deaths that occurred in the following year. Food prices also hit a high in Bihar during the year, even when compared with other north Indian states. For wheat and rice the prices in the state were twice or more than their prices in more prosperous Punjab. The government had “zoning” policies that prohibited trade of food across states; this reduced the availability of food in Bihar dramatically. In situations such as this, the poorest sections of the society suffered the most.

खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण किया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोज़ाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें भी काफी बढ़ी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूँ और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त ‘ज़ोनिंग’ या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वज़ह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। एसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The food crisis had many consequences. The government had to import wheat and had to accept foreign aid, mainly from the US. Now the first priority of the planners was to somehow attain self-sufficiency in food. The entire planning process and sense of optimism and pride associated with it suffered a setback.

खाद्य संकट के कई परिणाम हुए। सरकार को गेहूँ का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद (खासकर संयुक्त राज्य अमरीका की) भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना-प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा तथा गर्वबोध को इन बातों से एक धक्का लगा।

The Green Revolution

In the face of the prevailing food-crisis, the country was clearly vulnerable to external pressures and dependent on food aid, mainly from the United States. The United States, in turn, pushed India to change its economic policies. The government adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency. Instead of the earlier policy of giving more support to the areas and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well-off.

हरित क्रांति

खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य-सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमरीका के। संयुक्त राज्य अमरीका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए ज़ोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू-शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The argument was that those who already had the capacity could help increase production rapidly in the short run. Thus the government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides and better irrigation at highly subsidised prices. The government also gave a guarantee to buy the produce of the farmers at a given price. This was the beginning of what was called the 'green revolution'.

इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज़ रफ़्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे 'हरित क्रांति' कहा जाता है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

The rich peasants and the large landholders were the major beneficiaries of the process. The green revolution delivered only a moderate agricultural growth (mainly a rise in wheat production) and raised the availability of food in the country, but increased polarisation between classes and regions.

इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भू-स्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ (ज़्यादातर गेहूँ की पैदावार बढ़ी) और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ातरी हुई। बहरहाल, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग-अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज़ हुआ।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Some regions like Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh became agriculturally prosperous, while others remained backward. The green revolution had two other effects: one was that in many parts, the stark contrast between the poor peasantry and the landlords produced conditions favourable for leftwing organisations to organise the poor peasants.

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भू-स्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Secondly, the green revolution also resulted in the rise of what is called the middle peasant sections. These were farmers with medium size holdings, who benefited from the changes and soon emerged politically influential in many parts of the country.

दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भू-स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ । इन्हें बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

You must be familiar with the jingle 'utterly butterly delicious' and the endearing figure of the little girl holding a buttered toast. Yes, the Amul advertisements! Did you know that behind Amul products lies a successful history of cooperative dairy farming in India. Verghese Kurien, nicknamed the 'Milkman of India', played a crucial role in the story of Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Ltd that launched Amul.

‘अटरली बटरली डेलीशियस’ का जुमला आपने ज़रूर पढ़ा-सुना होगा और वह खुशगवार तसवीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी-सी बच्ची के हाथ में मक्खन लगा टोस्ट होता है। जी हां! हम ‘अमूल’ के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ‘अमूल’ के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है। ‘मिल्कमैन ऑफ़ इंडिया’ के नाम से मशहूर वर्गीज कूरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभायी और ‘अमूल’ की शुरुआत की।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Based in Anand, a town in Gujarat, Amul is a dairy cooperative movement joined by about 2 and half million milk producers in Gujarat. The Amul pattern became a uniquely appropriate model for rural development and poverty alleviation, spurring what has come to be known as the White Revolution. In 1970 the rural development programme called Operation Flood was started. Operation Flood organised cooperatives of milk producers into a nationwide milk grid,

गुजरात का एक शहर है 'आणंद'। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध-उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण-विकास और गरीबी-उन्मूलन के लिहाज से 'अमूल' नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस 'मॉडल' के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। 'ऑपरेशन फ्लड' के अंतर्गत सहकारी दूध-उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

with the purpose of increasing milk production, bringing the producer and consumer closer by eliminating middlemen, and assuring the producers a regular income throughout the year. Operation Flood was, however, not just a dairy programme. It saw dairying as a path to development, for generating employment and income for rural households and alleviating poverty. The number of members of the cooperative has continued to increase with the numbers of women members and Women's Dairy Cooperative Societies also increasing significantly.

बहरहाल, 'ऑपरेशन फ्लड' सिर्फ डेयरी-कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। सहकारी दूध-उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

Later developments

The story of development in India took a significant turn from the end of 1960s. You will see in Chapter Five how after Nehru's death the Congress system encountered difficulties. Indira Gandhi emerged as a popular leader. She decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. The period from 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industry. Fourteen private banks were nationalised. The government announced many pro-poor programmes. These changes were accompanied by an ideological tilt towards socialist policies. This emphasis generated heated debates within the country among political parties and also among experts.

बाद के बदलाव

1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। पाँचवें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस-प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गाँधी जननेता बनकर उभरीं। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएँ आयद हुईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चलीं। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चलीं।

Politics Of Planned Development नियोजित विकास की राजनीति

However, the consensus for a state-led economic development did not last forever. Planning did continue, but its salience was significantly reduced. Between 1950 and 1980 the Indian economy grew at a sluggish per annum rate of 3 to 3.5%. In view of the prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and the not-so-positive role of the bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith it initially placed in many of these institutions. Such lack of public faith led the policy makers to reduce the importance of the state in India's economy from the 1980s onwards. We shall look at that part of the story towards the end of this book.

बहरहाल, सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा लेकिन इसके महत्त्व में कमी आई। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3-3.5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का ज़ोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू-शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति-निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे।